



The
ACHIEVERS
IAS ACADEMY
PATNA

Daily
NEWS CHRONICLE

IDEAL FOR

For UPSC/BPSC & For other Exams

Hindi

NEWS CREDIT

PIB/ PTI/ News On Air/ The Hindu/ IANS/ Business Standard/ Times Of India/ Deccan Herald/ Hindustan Times/ BBC News/ Aljazeera/ Mirror.Uk/ Times Now/ Economic Times/ Financial Express/ Indian Express...

NEWS COVERED

Business News, financial news, economy news, company news, politics news, India news, breaking news, Indian economy, International News, Sports News, and many more topics...



Monday, August 10, 2026



+91 8434931877



www.achieversiaspatna.co.in



achieversiaspatna@gmail.com

दिन की प्रमुख घटनाएं

- **एनयूसीएफडीसी** ने देश भर में शहरी सहकारी बैंकों के लिए साइबर सुरक्षा केंद्र और सहकार सीबीएस लॉन्च किया।
- भारत ने वैश्विक आईपीओ नेतृत्व को **बरकरार रखा**, दुनिया भर में जुटाए गए धन में तीसरे स्थान पर है।
- ताशकंद में एशियाई युवा भारोत्तोलन चैंपियनशिप में तितली माजी ने रजत पदक जीता।
- लोकसभा ने **देश भर में विवाद के त्वरित समाधान के लिए एमएसएमई** विधेयक पारित किया।
- असम ने छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए **निजुत मोइना** और **निजुत बाबू योजनाएं** शुरू कीं।
- **ट्रेविस हेड** ने कैरी पर एक वोट की जीत के बाद लगातार एलन बॉर्डर मेडल जीता।
- **अमरीकी सीनेट** ने भारत और चीन पर शुल्क लगाने की अनुमति देने वाले प्रतिबंध विधेयक को मंजूरी दी।
- पश्चिम एशिया तनाव के बीच **तुर्किए, सऊदी अरब और पाकिस्तान** ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- **अबेलाडो डे ला एस्पिरएला** कोलंबिया के राष्ट्रपति बने, सुरक्षा कार्रवाई का वादा किया।
- डिजिलॉकर ने **सुरक्षित ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए AAERI** सत्यापन लॉन्च किया।
- 16वें वित्त आयोग ने संघवाद को मजबूत करते हुए राज्यों के लिए **41 प्रतिशत कर** हिस्सेदारी की सिफारिश की।

एनयूसीएफडीसी साइबर सुरक्षा और कोर बैंकिंग के माध्यम से शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करेगा



- सहकारिता मंत्रालय ने घोषणा की कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड (NUCFDC) शहरी सहकारी बैंकों (UCB) के लिए एक सुरक्षा संचालन केंद्र (SOC) और एक राष्ट्रव्यापी कोर बैंकिंग सेवा (सहकार CBS) शुरू करेगा।
- NUCFDC और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) के बीच एक समझौता ज्ञापन इस क्षेत्र में साइबर सुरक्षा और तकनीकी क्षमताओं को भी मजबूत करेगा।
- इन पहलों का उद्देश्य यूसीबी को आधुनिक, सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी और डिजिटल रूप से सक्षम बनाना है।

- NUCFDC क्या है?
- एनयूसीएफडीसी शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक छत्र संगठन है।

इसका उद्देश्य यूसीबी प्रदान करना है:

- साझा प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म।
- कोर बैंकिंग सेवाएं।
- साइबर सुरक्षा समाधान।
- क्षमता निर्माण समर्थन।
- परिचालन सहायता।

- यह साझा-सेवा मॉडल छोटे यूसीबी को ऐसी तकनीक तक पहुंचने में मदद कर सकता है जो अन्यथा व्यक्तिगत रूप से विकसित करना महंगा हो सकता है।

कोर बैंकिंग सिस्टम क्या है?

- कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) एक केंद्रीकृत बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो ग्राहकों को शाखाओं और चैनलों में बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाता है।
- लाभ: वास्तविक समय के लेनदेन, केंद्रीकृत रिकॉर्ड, डिजिटल बैंकिंग, इंटरऑपरेबिलिटी और बेहतर परिचालन दक्षता।

भारत ने आईपीओ में वैश्विक नंबर 1 स्थान बरकरार रखा: सेबी रिपोर्ट

शहरी सहकारी बैंक

- शहरी सहकारी बैंक मुख्य रूप से शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने वाले सहकारी बैंक हैं। वे सहकारी कानून द्वारा शासित होते हैं, लेकिन उनके बैंकिंग कार्यों को लागू बैंकिंग ढांचे के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनियमित किया जाता है।
- बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 ने सहकारी बैंकों पर RBI की नियामक और पर्यवेक्षी शक्तियों को मजबूत किया।

संबंधित संस्थान:

राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU):

- एनयूसीएफडीसी-एनएफएसयू सहयोग बैंकिंग क्षेत्र में साइबर सुरक्षा और तकनीकी क्षमता निर्माण के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। एनएफएसयू एक विशेष संस्थान है जो फॉरेंसिक विज्ञान, साइबर सुरक्षा और संबंधित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है।

जमा बीमा:

- पात्र सहकारी बैंकों में जमा राशि जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा कवर की जाती है, जिसमें प्रति बैंक प्रति जमाकर्ता 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर लागू नियमों के अधीन होता है।

परीक्षा फोकस बिंदु:

- एनयूसीएफडीसी: शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए छाता निकाय।
- सहकार सीबीएस: यूसीबी के लिए साझा कोर बैंकिंग प्रणाली।
- एसओसी: यूसीबी की साइबर सुरक्षा को मजबूत करता है।
- समझौता ज्ञापन: साइबर सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के लिए एनयूसीएफडीसी-एनएफएसयू।
- नियामक: आरबीआई।
- जमा बीमा: डीआईसीजीसी – प्रति बैंक प्रति जमाकर्ता ₹5 लाख।
- पॉलिसी लिंक: सहकार से समृद्धि।

- SEBI की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार, भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) की संख्या के मामले में शीर्ष

वैश्विक स्थिति बनाए रखी, जबकि जुटाए गए धन में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा। यह वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के पूंजी बाजारों के लचीलेपन को दर्शाता है।



मुख्य विचार:

IPO में ग्लोबल रैंक: मुद्रों की संख्या के हिसाब से 1.
जुटाए गए फंड में वैश्विक रैंक: 3
प्राथमिक इक्विटी बाजार: वित्त वर्ष 2025–26 में मजबूत बना रहा।
कॉर्पोरेट बॉन्ड मोबिलाइजेशन: 8.4% से ₹9.1 लाख करोड़ तक अस्वीकार कर दिया गया.
सार्वजनिक ऋण निर्गमन: लगभग 39% की वृद्धि।
म्यूनिसिपल बॉन्ड: 14 इश्यू के माध्यम से ₹1,756 करोड़ जुटाए गए।
DII इक्विटी होल्डिंग: मार्च 2026 तक रिकॉर्ड 17% तक पहुंच गया।
एफपीआई ओनरशिप: 15 साल के निचले स्तर पर गिर गया.

सेबी की महत्वपूर्ण पहल:

सेबी ने निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव/शुरुआत की है जिनमें शामिल हैं:

बेहतर कीमत की खोज के लिए समापन नीलामी सत्र (सीएस)।
निवेशक जागरूकता के लिए प्रोजेक्ट जगरूक।
सेबी सेतु पोर्टल।
सरलीकृत नामांकन मानदंड।
वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के लिए फास्ट-ट्रैक तंत्र।
डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (डीएलटी) का उपयोग करके कॉर्पोरेट बॉन्ड के टोकनाइजेशन के लिए पायलट प्रोजेक्ट।

तितली माजी ने महिलाओं के 45 किग्रा भारोत्तोलन में रजत पदक जीता

भारतीय भारोत्तोलक तितली माजी ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में महिलाओं के 45 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता।
--

सेबी:

स्थापना: 1988 एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में।
वैधानिक स्थिति: सेबी अधिनियम, 1992 के तहत 1992।
मुख्यालय: मुंबई।
अध्यक्ष: तुहिन कांता पांडे
भूमिका: भारत के प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करता है और निवेशकों की सुरक्षा करता है।

आईपीओ:

- इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) एक निजी रूप से आयोजित कंपनी के शेयरों की पहली सार्वजनिक बिक्री है, जो इसे सार्वजनिक निवेशकों से पूंजी जुटाने की अनुमति देती है.

प्राथमिक बनाम द्वितीयक बाजार:

प्राथमिक बाजार: नई पूंजी जुटाने के लिए नई प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं।
द्वितीयक बाजार: मौजूदा प्रतिभूतियों का निवेशकों के बीच कारोबार किया जाता है।

परीक्षा फोकस बिंदु:

रिपोर्ट: सेबी की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26।
वर्तमान रैंक: भारत - आईपीओ की संख्या में वैश्विक स्तर पर नंबर 1।
जुटाई गई धनराशि: विश्व स्तर पर तीसरा।
सेबी अधिनियम: 1992
नया बाजार तंत्र: नीलामी सत्र बंद करना।
म्यूनिसिपल बॉन्ड: 14 इश्यू के माध्यम से ₹1,756 करोड़।
DII होल्डिंग: मार्च 2026 में रिकॉर्ड 17%।
मुख्य विषय: पूंजी बाजार + आईपीओ + निवेशक सुरक्षा + वित्तीय समावेशन।

- उन्होंने कुल 145 किग्रा वजन उठाया, जिसमें स्नैच में 65 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 80 किग्रा शामिल थे।
- भारतीय भारोत्तोलक परिशमिता गोगोई इसी श्रेणी में चौथे स्थान पर रहीं।

भारोत्तोलन के बारे में:

भारोत्तोलन में दो प्रतिस्पर्धी लिफ्ट होते हैं:

- स्नैच: बारबेल को एक निरंतर आंदोलन में जमीन से ऊपर की ओर उठाया जाता है।
- क्लीन एंड जर्क: बारबेल को पहले कंधों पर लाया जाता है (साफ) और फिर ऊपर की ओर (झटका) उठाया जाता है।
- एथलीट का कुल योग सर्वश्रेष्ठ सफल स्नैच और क्लीन एंड जर्क का संयुक्त भार है।



भारत में भारोत्तोलन:

- कर्णम मल्लेश्वरी 2000 सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं।
- मीराबाई चानू ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में महिलाओं के 49 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता।
- राष्ट्रमंडल और एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिताओं में भारत की मजबूत उपस्थिति है।

अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय:

- अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ (IWF) भारोत्तोलन के लिए वैश्विक शासी निकाय है।
- भारोत्तोलन एक ओलंपिक खेल है।
- गठन: 10 जून 1905
- स्थापित: डुइसबर्ग, जर्मनी
- मुख्यालय: लुसाने, स्विट्जरलैंड
- राष्ट्रपति: मोहम्मद हसन जलौद (इराक)

परीक्षा फोकस बिंदु:

- वर्तमान उपलब्धि: तितली माजी – रजत, महिला 45 किग्रा।
- आयोजन: एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026
- मेजबान शहर: ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
- कुल लिफ्ट: 145 किग्रा।
- दो लिफ्ट: स्नैच + क्लीन एंड जर्क।
- पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता: कर्णम मल्लेश्वरी।
- टोक्यो 2020 भारोत्तोलन रजत: मीराबाई चानू।
- अंतर्राष्ट्रीय निकाय: आईडब्ल्यूएफ।

एमएसएमई विकास (संशोधन) विधेयक, 2026: एमएसएमई को विलंबित भुगतान से निपटना



- लोकसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया, ताकि एमएसएमई को विलंबित भुगतान की लगातार समस्या का समाधान किया जा सके और विवाद समाधान में तेजी लाई जा सके। इससे पहले इस विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी थी।
- एक प्रमुख प्रावधान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरडीडीएस) के माध्यम से खरीद चालान का निपटान करना अनिवार्य बनाता है, जिससे एमएसएमई के लिए तरलता में सुधार होता है।

प्रमुख प्रावधान:

- टीआरडीडीएस: पात्र एमएसएमई खरीद चालान के निपटान के लिए सीपीएसई द्वारा अनिवार्य उपयोग।
- विवाद समाधान: मध्यस्थता 90 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी।
- विलंबित अपील: यदि कोई अपील छह महीने से अधिक समय तक लंबित रहती है, तो अदालतों को एमएसएमई को दी गई राशि का कम से कम 50% जारी करने की आवश्यकता हो सकती है।
- गैर-अपराधीकरण: मामूली पंजीकरण/रिपोर्टिंग चूक को आपराधिक दायित्व से श्रेणीबद्ध प्रशासनिक चेतावनियों और मौद्रिक दंड में स्थानांतरित कर दिया गया।
- जुर्माना सीमा: निर्दिष्ट मामूली चूक के लिए ₹1,000 से ₹1 लाख।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

- विलंबित भुगतान एमएसएमई के लिए गंभीर कार्यशील पूंजी और तरलता की समस्या पैदा करता है, खासकर क्योंकि छोटे उद्यमों के पास किफायती वित्त तक सीमित पहुंच होती है। विधेयक का उद्देश्य नकदी प्रवाह में सुधार, व्यापार करने में आसानी, प्राप्तियों के वित्तपोषण को औपचारिक रूप देना और एमएसएमई की वित्तीय स्थिरता को मजबूत करना है।

TReDS क्या है?

- ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो एमएसएमई को बैंकों और अन्य अनुमत फाइनेंसर्स द्वारा वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करके अपनी व्यापार प्राप्तियों को तत्काल धन में बदलने में सक्षम बनाता है।
- महत्व: यह भुगतान के लिए प्रतीक्षा अवधि को कम करता है और पारंपरिक ऋणों पर पूरी तरह से निर्भर हुए बिना कार्यशील पूंजी प्रदान करता है।

भारत में MSME

- एमएसएमई क्षेत्र रोजगार सृजन, निर्यात, विनिर्माण और समावेशी औद्योगीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। सरकारी आंकड़ों पर प्रकाश डाला गया है कि एमएसएमई सकल घरेलू उत्पाद में 31 प्रतिशत से अधिक और निर्यात में लगभग 48.58 प्रतिशत का योगदान करते हैं, जबकि लगभग 328 मिलियन लोगों को आजीविका प्रदान करते हैं।

वर्तमान एमएसएमई वर्गीकरण

कोटि खरीदी वस्तुवार्षिक टर्नओवर		
लघुस्तरीय	₹2.5 करोड़ तक	₹10 करोड़ तक
मामूली	₹25 करोड़ तक	₹100 करोड़ तक
मध्यम	₹125 करोड़ तक	₹500 करोड़ तक

संबंधित सरकारी पहल:

- एमएसएमई समाधान: एमएसएमई को खरीदारों के खिलाफ विलंबित भुगतान के संबंध में आवेदन दायर करने में सक्षम बनाने वाला एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म।
- जीईएम: सरकारी ई-मार्केटप्लेस एमएसएमई सहित व्यवसायों से सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा पारदर्शी ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करता है।
- RAMP: MSME प्रदर्शन को बढ़ाना और तेज करना (RAMP) बाजारों, वित्त, प्रौद्योगिकी और संस्थागत क्षमता तक बेहतर पहुंच का समर्थन करता है।

अतिरिक्त तथ्य:

एमएसएमई विकास अधिनियम: 2006
नोडल मंत्रालय: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय।
अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस: 27 जून
ट्रेड्स नियामक: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)।
टीआईडीएस का उद्देश्य: एमएसएमई व्यापार प्राप्तियों का वित्तपोषण/छूट।
एमएसएमई समाधान: विशेष रूप से विलंबित भुगतान शिकायतों पर ध्यान केंद्रित करता है।

परीक्षा फोकस बिंदु -

वर्तमान मुद्दा: एमएसएमई विकास (संशोधन) विधेयक, 2026
मुख्य चिंता: विलंबित भुगतान और तरलता की कमी।
मुख्य मंच: ट्रेड्स।
विवाद समयरेखा: 90 दिनों के भीतर मध्यस्थता।
अपील प्रावधान: छह महीने के बाद प्रदान की गई राशि का 50%, बिल के प्रावधानों के अधीन।
सुधार विषय: व्यापार करने में आसानी + गैर-अपराधीकरण + एमएसएमई तरलता।

असम ने निजुत मोइना और निजुत बाबू योजनाएं शुरू की



- असम सरकार ने मुख्यमंत्री मंत्री निजुत मोइना असोनी और मुख्यमंत्री निजुत बाबू असोनी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसका उद्देश्य छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और निरंतर शिक्षा को बढ़ावा देना है।
- इन योजनाओं का शुभारंभ मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में किया।

निजुत मोइना योजना:

- निजुत मोइना असोनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य लड़कियों को अपनी

पढ़ाई जारी रखने, उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में सुधार करने और बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। असम उच्च शिक्षा निदेशालय ने योजना के लिए 2026 दिशानिर्देश जारी किए हैं।

निजुत बाबू योजना:

- आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पुरुष छात्रों को निजुत बाबू असोनी वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। यह उच्च शिक्षा जारी रखने में योग्य छात्रों का समर्थन करने और अकादमिक प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। 2026 के दिशानिर्देश असम के उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किए गए हैं।

असम:

राजधानी: दिसपुर
प्रमुख नदी: ब्रह्मपुत्र
राज्य का दर्जा: 26 जनवरी 1950
महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान: काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
मुख्यमंत्री: हिमंत बिस्वा सरमा
राज्यपाल: लक्ष्मण प्रसाद आचार्य
यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल: काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभयारण्य

संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

अनुच्छेद 21A: 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
अनुच्छेद 45: प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा।
अनुच्छेद 46: कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना।

परीक्षा फोकस बिंदु:

वर्तमान अंक: असम ने निजुत मोइना और निजुत बाबू के लिए आवेदन शुरू किए।
निजुत मोइना: छात्राओं के लिए वित्तीय सहायता।
निजुत बाबू: आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पुरुष छात्रों के लिए वित्तीय सहायता।
राज्य: असम।
कार्यान्वयन विभाग: उच्च शिक्षा निदेशालय, असम।
मुख्य उद्देश्य: उच्च शिक्षा तक पहुंच, वित्तीय सहायता और ड्रॉपआउट में कमी।

ट्रेविस हेड ने लगातार दूसरा एलन बॉर्डर मेडल जीता



यह खबरों में क्यों है?

- ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ट्रेविस हेड ने लगातार दूसरे साल एलन बॉर्डर मेडल जीता है। उन्होंने टीम के साथी एलेक्स कैरी को एक वोट से हराया और लगातार वर्षों में प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले केवल पांचवें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बन गए।

मुख्य बिंदु

विजेता: ट्रेविस हेड
पुरस्कार: एलन बॉर्डर मेडल 2026

- उपलब्धि: लगातार दूसरे वर्ष पुरस्कार जीता।
- करीबी प्रतिस्पर्धा: हेड ने एलेक्स कैरी को सिर्फ एक वोट से हराया।
- ऐतिहासिक उपलब्धि: लगातार वर्षों में पदक जीतने वाले पांचवें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बने।

एलन बॉर्डर मेडल के बारे में

- एलन बॉर्डर मेडल ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च व्यक्तिगत पुरुष क्रिकेट पुरस्कार है। यह ऑस्ट्रेलियाई पुरुष क्रिकेटर को हर साल प्रस्तुत किया जाता है, जिसे मतदान अवधि के दौरान अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए आंका जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

एलन बॉर्डर, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और ऑस्ट्रेलिया के महानतम क्रिकेटरों में से एक।
द्वारा सम्मानित किया गया: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों के हिस्से के रूप में।
पहली बार सम्मानित: 2000।

- श्रेणी: सर्वश्रेष्ठ ऑस्ट्रेलियाई पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर। - प्रारूप पर विचार किया गया: टेस्ट, वनडे और टी20 क्रिकेट। - मतदान: वोट खिलाड़ियों, अंपायरों और मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा दिए जाते हैं। - वेटेज: मौजूदा प्रणाली के तहत टेस्ट वोट 2×, वनडे वोट 1× और टी20 वोट 3× होते हैं। - महिला समकक्ष: बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार।	हाल के विजेता: ट्रेविस हेड (2025), मिच मार्श (2024), स्टीव स्मिथ (2023), मिशेल स्टार्क (2022)।
महत्व हेड की बैक-टू-बैक जीत ने उन्हें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों के एक विशिष्ट समूह में जगह दी। यह पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके लगातार प्रदर्शन को मान्यता देता है और उन्हें ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक के रूप में स्थापित करता है।	

अमेरिकी सीनेट ने भारत और चीन पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने की अनुमति देने वाले रूस प्रतिबंध विधेयक को मंजूरी दी



यह खबरों में क्यों है?

- अमेरिकी सीनेट ने रूस और उन देशों को लक्षित करने वाले एक नए विधेयक को मंजूरी दे दी है जो रूसी तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं। यह विधेयक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को उन देशों के सामानों पर 100% टैरिफ लगाने की अनुमति देता है जो भारत और चीन सहित रूसी तेल और गैस के शीर्ष पांच खरीदारों में से हैं।

मुख्य बिंदु

- इस विधेयक को अमेरिकी सीनेट ने 86-11 वोट से मंजूरी दे दी थी।
- इसे लिंडसे ओ. ग्राहम सेंकशंसिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 कहा जाता है।
- यह अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी तेल और गैस के प्रमुख खरीदारों से माल पर 100% टैरिफ लगाने की शक्ति देता है।
- वर्तमान में सूचीबद्ध शीर्ष पांच खरीदार चीन, भारत, अजरबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया हैं।
- विधेयक में रूसी नेताओं, अधिकारियों, कुलीन वर्गों और वित्तीय संस्थानों के खिलाफ प्रतिबंधों का भी प्रस्ताव है।
- यह 1996 के ईरान प्रतिबंध अधिनियम को 2031 तक बढ़ाता है।

पृष्ठभूमि

- अमेरिका यूक्रेन संघर्ष को लेकर रूस पर अधिक आर्थिक दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। वाशिंगटन का तर्क है कि रूसी ऊर्जा खरीदने वाले देश अप्रत्यक्ष रूप से रूस की अर्थव्यवस्था और उसके युद्ध प्रयासों का समर्थन करते हैं। हालांकि, भारत ने मुख्य रूप से ऊर्जा सुरक्षा और अनुकूल कीमतों के कारण रूसी कच्चे तेल की खरीद जारी रखी है।

भारत पर प्रभाव

- यदि प्रस्तावित टैरिफ शक्तियों का उपयोग भारत के खिलाफ किया जाता है, तो अमेरिका को भारतीय निर्यात काफी महंगा हो सकता है। यह कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान और अन्य निर्यात-उन्मुख उद्योगों जैसे क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। इससे भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों पर अतिरिक्त दबाव भी पड़ सकता है।

महत्व

- यह विधेयक भारत पर अपनी रूसी ऊर्जा खरीद पर पुनर्विचार करने के लिए आर्थिक और राजनयिक दबाव बढ़ा सकता है। साथ ही भारत को अपनी ऊर्जा-सुरक्षा जरूरतों, रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी और अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों को संतुलित करना होगा।

परीक्षा फोकस पॉइंट

बिल: लिंडसे ओ. ग्राहम रूस और ईरान अधिनियम, 2026 को मंजूरी देना।
द्वारा स्वीकृत: अमेरिकी सीनेट।
अधिकतम प्रस्तावित टैरिफ: 100%।
संभावित रूप से प्रभावित देश: भारत, चीन, अजरबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया।
मुख्य लक्ष्य: रूस और रूसी तेल और गैस के प्रमुख खरीदार।
अगला चरण: अमेरिकी प्रतिनिधि सभा।
भारत के लिए मुख्य मुद्दा: निर्यात और रूसी तेल आयात पर प्रभाव।

- ईरान प्रतिबंध अधिनियम: 2031 तक बढ़ाया गया।

आगे की राह

- भारत को अमेरिका के साथ राजनयिक जुड़ाव को आगे बढ़ाने, ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने, अपने निर्यात हितों की रक्षा करने और सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने की आवश्यकता होगी।

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने संयुक्त रक्षा समझौते की योजना बनाई



यह खबरों में क्यों है?

- तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान चल रहे अमेरिका-ईरान संघर्ष और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिए एक त्रिपक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं।

मुख्य बिंदु

- इस समझौते में तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान शामिल हैं।
- यह लगभग एक साल की बातचीत के बाद है।
- इस समझौते का उद्देश्य तीनों देशों के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग को मजबूत करना है।
- समझौते के तहत सटीक प्रतिबद्धताओं का शुरू में खुलासा नहीं किया गया था।
- तुर्किये नाटो का सदस्य है।
- सऊदी अरब अमेरिका का एक प्रमुख सहयोगी और प्रमुख तेल निर्यातक है।
- इन तीनों में से पाकिस्तान एकमात्र परमाणु संपन्न देश है।

पृष्ठभूमि:

- सऊदी-पाकिस्तान रक्षा समझौता
- सऊदी अरब और पाकिस्तान पहले ही सितंबर 2025 में एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके थे। उस समझौते के तहत एक देश पर हमले को दोनों पर हमले के रूप में माना जाता है।

एबेलाडो डी ला एस्पिरला कोलंबिया के राष्ट्रपति बने

यह खबरों में क्यों है?

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

नई त्रिपक्षीय व्यवस्था यह कर सकती है:

- क्षेत्रीय रक्षा सहयोग को मजबूत करना।
- तीनों देशों के बीच समन्वय में सुधार करें।
- पश्चिम एशिया में अस्थिरता के बीच अपनी सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना।
- संभावित रूप से खाड़ी और व्यापक पश्चिम एशिया में रणनीतिक संतुलन को प्रभावित करेगा।

परीक्षा फोकस पॉइंट

- बिंदु विवरण
- देशों तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान
- प्रकार त्रिपक्षीय रक्षा समझौता
- क्षेत्र पश्चिम एशिया/खाड़ी
- मुख्य उद्देश्य रक्षा सहयोग को मजबूत करना
- सऊदी-पाकिस्तान समझौता सितंबर 2025 में हस्ताक्षरित
- तुर्किये नाटो सदस्य
- पाकिस्तान परमाणु हथियारों से लैस राज्य
- सऊदी अरब प्रमुख तेल निर्यातक

- नोट: प्रारंभिक रिपोर्ट में समझौते को हस्ताक्षरित होने के रूप में वर्णित किया गया था; बाद की रिपोर्टिंग इस बात की पुष्टि करती है कि मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर 7 अगस्त 2026 को हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें पारस्परिक-रक्षा प्रतिबद्धता थी कि एक पर सशस्त्र हमला तीनों पर हमला माना जाता है।

- दक्षिणपंथी वकील और राजनीतिक नवागंतुक एबेलाडो डे ला एस्पिरला ने कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी और सशस्त्र समूहों पर सख्त कार्रवाई का वादा किया है।



मुख्य बिंदु

- नए राष्ट्रपति: एबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला।
- देश: कोलंबिया।
- शपथ ग्रहण: 7 अगस्त 2026।
- वह वामपंथी राष्ट्रपति गुस्तावो पेद्रो की जगह लेंगे।
- डे ला एस्प्रिएला ने सशस्त्र समूहों और नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ एक कठोर दृष्टिकोण का वादा किया है।
- उन्होंने सशस्त्र समूहों के साथ पिछली सरकार के संवाद-आधारित दृष्टिकोण को खारिज करते हुए कहा है कि बातचीत समाप्त हो गई है।
- वह सरकारी खर्च को कम करने, तेल और गैस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और निवेश का समर्थन करने की भी योजना बना रहे हैं।
- अमेरिका ने सुरक्षा सहायता में \$ 1 बिलियन की योजना की घोषणा की है, जो अमेरिकी कांग्रेस द्वारा अनुमोदन के अधीन है।

कोलंबिया में प्रमुख सशस्त्र समूह

कोलंबिया को कई सशस्त्र और आपराधिक समूहों से हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें शामिल हैं:

- ईएलएन (नेशनल लिबरेशन आर्मी)
- एफएआरसी असंतुष्ट समूह
- कबीले डेल गोलफो, एक प्रमुख नशीली दवाओं की तस्करी करने वाला संगठन।

महत्व

- डी ला एस्प्रिएला की जीत कोलंबिया की हालिया वामपंथी सरकार से दक्षिणपंथी राजनीतिक दृष्टिकोण की ओर एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी सरकार से राष्ट्रीय सुरक्षा, मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने, आर्थिक सुधारों और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंधों पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है।

परीक्षा फोकस पॉइंट

• बिंदु विवरण	
• नए राष्ट्रपति	एबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला
• भूक्षेत्र कोलंबिया	
• शपथ ली	7 अगस्त 2026
• पूर्व राष्ट्रपति	गुस्तावो पेद्रो
• मुख्य फोकस	सशस्त्र समूहों की सुरक्षा और कार्रवाई
• प्रमुख सशस्त्र समूह	ईएलएन, एफएआरसी असंतुष्ट, खाड़ी कबीले
• अमेरिकी सुरक्षा सहायता	1 अरब डॉलर प्रस्तावित
• प्रमुख आर्थिक फोकस	तेल, गैस, निवेश और खर्च में कटौती

डिजिटलॉकर ने भारतीय छात्रों के लिए ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय के आवेदनों को सरल बनाने के लिए 'एएईआरआई वेरिफाई' लॉन्च किया



यह खबरों में क्यों है?

- इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) ने 'AAERI सत्यापन' लॉन्च करने के लिए एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया (AAERI) के साथ भागीदारी की है। यह भारतीय छात्रों को ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में आवेदन करते समय अपने दस्तावेजों को डिजिटल रूप से सत्यापित करने में मदद करेगा।

मुख्य बिंदु

- प्लेटफॉर्म: AAERI सत्यापित करें
- भागीदार: एनईजीडी और एएईआरआई

के साथ एकीकृत: डिजिलॉकर
लक्ष्य समूह: ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में आवेदन करने वाले भारतीय छात्र
लॉन्च: 7 अगस्त 2026, नई दिल्ली
मुख्य उद्देश्य: छात्र दस्तावेजों का तेज और सुरक्षित सत्यापन।

AAERI सत्यापन कैसे काम करेगा?

- यह प्रणाली छात्रों को डिजिलॉकर के माध्यम से सीधे अपने मूल जारीकर्ता प्राधिकरणों से प्रामाणिक, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों को साझा करने की अनुमति देगी।

इसके दो चरण होंगे:

छात्र जांच: विश्वविद्यालय आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है।
प्रायोजक जांच: प्रवेश की पेशकश के बाद, छात्र के वित्तीय दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है।
छात्रों को अपने दस्तावेजों को ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के साथ साझा करने से पहले अपनी सहमति देनी होगी।

किन दस्तावेजों को सत्यापित किया जा सकता है?

प्लेटफ़ॉर्म सत्यापित करने में मदद करेगा:

शैक्षणिक रिकॉर्ड
पहचान दस्तावेज
वित्तीय/प्रायोजन रिकॉर्ड

लाभ

- कागजी कार्रवाई और मैन्युअल सत्यापन को कम करता है।
- दस्तावेज सत्यापन को तेज और अधिक सुरक्षित बनाता है।
- नकली या धोखाधड़ी वाले दस्तावेजों के जोखिम को कम करने में मदद करता है।

16वां वित्त आयोग: भारत में राजकोषीय संघवाद को मजबूत करना



- सहमति-आधारित साझाकरण के माध्यम से छात्र डेटा गोपनीयता की रक्षा करता है।
- भारतीय छात्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया को आसान बनाता है।

डिजिलॉकर के बारे में

- डिजिलॉकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन के तहत एक सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों को अधिकृत संस्थानों द्वारा जारी डिजिटल दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने, एक्सेस करने, साझा करने और सत्यापित करने की अनुमति देता है। इसे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया था और वर्तमान में इसके 72 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं।

परीक्षा फोकस पॉइंट

बिंदु विवरण	
नया मंच	AAERI सत्यापित करें
भारतीय भागीदार	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (एनईजीडी)
ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा भागीदार	एएईआरआई
प्रौद्योगिकी भागीदार	डिजिलॉकर
मंत्रालय	एमईआईटीवाई
लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया जा रहे भारतीय छात्र	
लॉच	7 अगस्त 2026
स्थान	नई दिल्ली
मुख्य उद्देश्य	डिजिटल दस्तावेज सत्यापन
सत्यापन	अकादमिक, पहचान और वित्तीय रिकॉर्ड
प्रमुख विशेषता	सहमति-आधारित सत्यापन

यह खबरों में क्यों है?

- 16वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि पांच साल की अवधि 2026-27 से 2030-31 के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों को कैसे साझा किया जाना चाहिए। इसकी सिफारिशें राजकोषीय संघवाद को मजबूत करने और केंद्र, राज्यों और स्थानीय सरकारों की वित्तीय जरूरतों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

वित्त आयोग क्या है?

- वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
- यह आम तौर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर पांच साल में या यदि आवश्यक हो तो उससे पहले गठित किया जाता है।

मुख्य कार्य

वित्त आयोग अनुशंसा करता है:

कर हस्तांतरण – केंद्र के कर राजस्व को केंद्र और राज्यों के बीच कैसे विभाजित किया जाना चाहिए।
राज्यों के बीच वितरण - राज्यों के हिस्से को अलग-अलग राज्यों के बीच कैसे विभाजित किया जाना चाहिए।
सहायता अनुदान - राज्यों को वित्तीय अनुदान देने के सिद्धांत।
स्थानीय निकाय - पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों को बढ़ाने के उपाय।
राजकोषीय अनुशासन - वित्तीय स्थिरता और जिम्मेदार सरकारी खर्च में सुधार के उपाय।

16वें वित्त आयोग के बारे में

विशेष	विवरण
संवैधानिक आधार	अनुच्छेद 280
गठित	2023
अध्यक्ष	अरविंद पनगढ़िया
पुरस्कार अवधि	2026–27 से 2030–31
मुख्य कार्य	केंद्र-राज्य वित्तीय वितरण
पिछला आयोग	15वां वित्त आयोग

मुख्य मुद्दा राजकोषीय संघवाद

राजकोषीय संघवाद क्या है?

राजकोषीय संघवाद से तात्पर्य सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच वित्तीय शक्तियों, जिम्मेदारियों और संसाधनों के विभाजन से है।
भारत में, तीन प्रमुख स्तर हैं:
केंद्र सरकार → राज्य सरकारें → स्थानीय सरकारें

उदाहरण के लिए:

- केंद्र आयकर और निगम कर जैसे प्रमुख कर एकत्र करता है।
- इन करों का एक हिस्सा राज्यों को हस्तांतरित किया जाता है।
- राज्य पंचायतों और नगरपालिकाओं को भी निधियां प्रदान करते हैं।
- इस प्रकार, राजकोषीय संघवाद यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के विभिन्न स्तरों के पास अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन हों।

16वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें

- राज्यों का कर हिस्सा – 41%
- आयोग ने केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों के हिस्से को 41 प्रतिशत पर बरकरार रखा है।
- इसका मतलब है कि राज्यों को साझा करने योग्य केंद्रीय कर पूल का 41% प्राप्त होता रहेगा।
- महत्वपूर्ण: इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यों को केंद्र द्वारा एकत्र किए गए प्रत्येक रुपये का 41% प्राप्त होता है। उपकर और अधिभार आम तौर पर विभाज्य पूल के बाहर होते हैं।

राज्यों के बीच वितरण

- राज्यों के हिस्से को विभिन्न मानदंडों का उपयोग करते हुए अलग-अलग राज्यों में विभाजित किया जाता है।

इनमें निम्नलिखित कारक शामिल हैं:

जनसंख्या
कार्य-क्षेत्र
वन क्षेत्र
जनसांख्यिकीय प्रदर्शन
आय से संबंधित संकेतक
आर्थिक विकास में योगदान
इसका उद्देश्य प्रदर्शन के साथ इक्विटी को संतुलित करना है।

राजकोषीय अनुशासन पर ध्यान

आयोग ने निम्नलिखित पर अधिक जोर दिया है:

अत्यधिक उधार को नियंत्रित करना
सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन
राजस्व संग्रह में सुधार
राजकोषीय स्थिरता बनाए रखना
जिम्मेदार सरकारी व्यय

- इसका उद्देश्य राज्यों को वित्तीय रूप से मजबूत और अधिक आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना है।

राजस्व-घाटा अनुदान

- आयोग ने इस अवधि के लिए कोई राजस्व-घाटा अनुदान नहीं देने की सिफारिश की है।
- राजस्व-घाटा अनुदान उन राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता है जिनकी राजस्व प्राप्तियां उनके राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं।
- इस कदम का उद्देश्य राज्यों को अपने स्वयं के राजस्व सृजन और व्यय प्रबंधन में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

स्थानीय सरकारों के लिए अधिक समर्थन

वित्त आयोग निम्नलिखित को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है:

- पंचायती राज संस्थाएं
- नगर पालिकाएं
- ग्रामीण स्थानीय निकाय
- शहरी स्थानीय निकाय
- स्थानीय सरकारों को पर्याप्त धन देना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे स्वच्छता, स्थानीय सड़कों, जल आपूर्ति और बुनियादी ढांचे जैसी सेवाओं के लिए जिम्मेदार हैं।

16वां वित्त आयोग क्यों महत्वपूर्ण है?

- आयोग को दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा:
- समानता: कम विकसित राज्यों को सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।
- दक्षता: राज्यों को अपने आर्थिक प्रदर्शन, राजस्व सृजन और राजकोषीय प्रबंधन में सुधार करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसलिए, वित्त आयोग केवल धन वितरित करने के बारे में नहीं है। यह केंद्र और राज्यों के बीच एक निष्पक्ष और स्थायी वित्तीय संबंध बनाने के बारे में भी है।

केंद्र बनाम राज्य: कर हस्तांतरण को समझना

- केंद्र सरकार टैक्स वसूलती है
- ↓
- केंद्रीय करों का विभाज्य पूल
- ↓
- 41% राज्यों को हस्तांतरित
- ↓
- राज्यों का हिस्सा अलग-अलग राज्यों में वितरित किया गया
- यह व्यवस्था भारत के सहकारी संघवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

मुख्य चिंता

- केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंधों में एक प्रमुख मुद्दा उपकर और अधिभार का बढ़ता महत्व है।
- चूंकि ये आम तौर पर विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए राज्यों का तर्क है कि कुल केंद्रीय कर संग्रह में उनका प्रभावी हिस्सा हेडलाइन 41% हस्तांतरण के आंकड़े से कम हो सकता है।
- यह कर हस्तांतरण, राजकोषीय स्वायत्तता और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों को बहस का महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाता है।

परीक्षा फोकस पॉइंट

प्रश्न क्षेत्र	हल
वित्त आयोग का संवैधानिक आधार	अनुच्छेद 280
16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया	
आयोग का गठन	2023
पुरस्कार की अवधि	2026–27 से 2030–31
विभाज्य कर पूल में राज्यों की हिस्सेदारी	41%
मुख्य अवधारणा	राजकोषीय संघवाद
पिछला आयोग	15वां वित्त आयोग
द्वारा नियुक्त	भारत के राष्ट्रपति
आवृत्ति	आम तौर पर हर 5 साल में
स्थानीय निकायों को कवर किया गया	पंचायतें और नगर पालिकाएं

लेट्स रिवाइज

- ❖ साइबर सुरक्षा और तकनीकी क्षमता निर्माण के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए NUCFDC ने हस्ताक्षर किए? **राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU)**
- ❖ किस देश ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान आईपीओ की संख्या में दुनिया का शीर्ष स्थान बरकरार रखा? **भारत**
- ❖ 2026 एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 45 किग्रा वर्ग में किसने रजत पदक जीता? **तितली माजी**
- ❖ एमएसएमई खरीद चालान के निपटान के लिए नए तंत्र के लिए किस मंच को केंद्रीय बनाया गया है? **ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS)**
- ❖ किस राज्य सरकार ने निजत मोइना और निजुत बाबू योजनाएं शुरू कीं? **असम सरकार**
- ❖ एलन बॉर्डर मेडल 2026 किसने जीता? **ट्रेविस हेड**
- ❖ एलन बॉर्डर मेडल क्या है? **यह ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च व्यक्तिगत पुरुष क्रिकेट पुरस्कार है।**
- ❖ एलन बॉर्डर मेडल पहली बार कब प्रदान किया गया था? **2000**
- ❖ रूस और उसके प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के खिलाफ अमेरिकी सीनेट द्वारा अनुमोदित विधेयक का नाम क्या है? **लिंगसे ओ. ग्राहम रूस और ईरान अधिनियम, 2026 को मंजूरी देते हैं।**
- ❖ 2026 में किन तीन देशों ने त्रिपक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? **तुर्किए, सऊदी अरब और पाकिस्तान**
- ❖ तुर्किए-सऊदी अरब-पाकिस्तान रक्षा समझौते में, तीनों में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? **तुर्किए**
- ❖ कोलंबिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? **एबेलाडो डे ला एस्पिरला**
- ❖ कोलंबिया में सक्रिय तीन प्रमुख सशस्त्र या आपराधिक समूहों के नाम बताइए; **ईएलएन, एफएआरसी असंतुष्ट समूह और कबीले डेल गोल्फो**
- ❖ 'AAERI सत्यापन' क्या है? **यह ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में आवेदन करने वाले भारतीय छात्रों के लिए एक डिजिटल दस्तावेज सत्यापन मंच है।**
- ❖ 'AAERI Verify' को किसने लॉन्च किया? **नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) और एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया (एईआरआई)**
- ❖ AAERI Verify किस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत है? **डिजिलॉकर**
- ❖ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है? **अनुच्छेद 280**
- ❖ वित्त आयोग का गठन कौन करता है? **भारत के राष्ट्रपति**
- ❖ वित्त आयोग का गठन आम तौर पर कितनी बार किया जाता है? **हर पांच साल में या उससे पहले, यदि आवश्यक हो।**
- ❖ 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? **अरविंद पनगढ़िया**
- ❖ 16वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? **2023**



The **ACHIEVERS** IAS ACADEMY PATNA

Daily **NEWS CHRONICLE**

IMPORTANCE OF CURRENT AFFAIRS IN UPSC EXAMINATIONS

Current Affairs hold a crucial place in the preparation for the UPSC Civil Services Examination. A comprehensive understanding of recent national and international developments helps aspirants strengthen their General Studies foundation and develop a well-rounded perspective on important issues. Topics such as government policies, schemes, economy, international relations, science and technology, environment, defence, social justice, governance, reports, indices, appointments, awards, and major global events are highly relevant for both the Prelims and Mains examinations. Regular study of current affairs not only enhances factual knowledge but also improves analytical ability, critical thinking, answer-writing skills, and decision-making aptitude. Since UPSC questions often connect contemporary developments with static subjects, consistent preparation of current affairs enables aspirants to understand issues in depth and present balanced, informed, and relevant answers. It also plays an important role in Essay writing, Ethics, and the Personality Test, giving candidates a strong edge throughout the examination process.

CONTACT US



+91 8434931877



achievers_ias_patna



PATLIPUTRA GOLAMBAR



ACHIEVERS IAS ACADEMY (UPSC/BPSC)



achieversiaspatna@gmail.com



Achievers IAS Academy



www.achieversiaspatna.co.in



Achievers IAS Academy, PATNA